जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 28 संख्याः 130 प्रभात अजमेर, शनिवार 9 दिसम्बर, 2023 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राहुल गांधी ने विदेश यात्रा का कार्यक्रम स्थगित किया

वे शनिवार को राजस्थान में चुनावी हार की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में भाग लेंगे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। शनिवार को राजस्थान विधानसभा चुनावों की हार पर मंथन के लिए होने वाली बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे।

यह मीटिंग शनिवार सुबह नई दिल्ली के ए.आई.सी.सी. मुख्यालय में होगी।

राहुल गांधी आज रात विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले थे, पर पार्टी के कुछ शुभचिंतकों की सलाह पर विदेश यात्रा कुछ समय के लिए रद्द कर दी गई है। राहुल को इन नेताओं ने सलाह दी है कि विदेश जाने का यह सही समय नहीं है।

आज शुक्रवार को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बैठक हुई। इसमें भी राहुल और खड़गे मौजूद थे। कांग्रेस, राजस्थान के साथ इन दोनों राज्यों में भी हार गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री मीटिंग में शामिल होने दिल्ली पहुंच रहे हैं और वे नेतृत्व को हार के कारणों की जानकारी देंगे।

- अशोक गहलोत, सचिन पायलट आदि वरिष्ठ नेता मीटिंग में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं।
- समीक्षा बैठक ए.आई.सी.सी. मुख्यालय में शनिवार को सुबह आयोजित की गई है।
- शुक्रवार को छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में हुई हार की समीक्षा के लिए भी बैठक आयोजित की गई, जिसमें राहुल गांधी व पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे।
- बैठक में हार के कारणों पर जवाब तलब किए जाएंगे और अशोक गहलोत हार की जिम्मेवारी खुद लेने की बजाय भाजपा पर दोषारोपण करने की कोशिश करेंगे।

सचिन पायलट व अन्य नेताओं को भी बुलाया गया है जो पहले ही आ चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि गहलोत की दलील है कि भाजपा द्वारा किये गये ध्रुवीकरण की वजह से पार्टी की हार हुई है।

वे भाजपा को हार का जिम्मेवार ठहरा रहे है, बजाय अपनी गलती स्वीकारने के। आज़ादी के बाद से यह कांग्रेस की तीसरी करारी हार है। पहली हार 2013 में हुई थी जब कांग्रेस सिर्फ 21 सीटें जीत पाई थी, 2013 में कांग्रेस ने 54 सीटें जीती थी और इस बार 69 सीटें जीती हैं और तीनों बार अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था।

गहलोत को लगता है कि उनका जन्म राज करने के लिए ही हुआ है। वे अपने किसी विश्वस्त को विधायक दल का नेता बनाना चाहते हैं ताकि कांग्रेस पर उनकी पकड़ बनी रहे। गहलोत के दो अन्य विश्वस्तों गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से तथा रंधावा ने प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इन दोनों को गहलोत की आवाज़ और छाया माना जाता है।

प्रदेश इकाई में कोई भी परिवर्तन हार के कारणों पर मंथन होने के बाद ही होगा। लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या यह मीटिंग गंभीर कवायद होगी या मात्र टाइम पास मीटिंग होगी। क्या नेतृत्व वास्तव में उन गलतियों को सुधारने के प्रति गंभीर है जो कांग्रेस सिस्टम में घुस गई है और पार्टी के काम काज को प्रभावित कर रही हैं।

'आई.सी.आई.सी.आई. बैंक सी.ई.ओ. चंदा कोचर की बर्खास्तगी सही'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की सी.ई.ओ. चन्दा कोचर के बर्खास्त करने को सही माना और उनके सेवानिवृति के लाभ तथा स्टाक ऑप्शन समाप्त करने के 2019 के निर्णय की पुष्टी की। जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली बैंच के निर्णय ने, जो शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया, पूर्व के हाई कोर्ट निर्णय का समर्थन किया, जिसमें कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया। पद्म भूषण से सम्मानित चंदा कोचर पर पद का दुरूपयोग कर अपने पति दीपक कोचर को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है।

के सेवानिवृति के लाभ अथवा एम्पलायी स्टाक ओनर शिप प्लान (ई.एस.ओ.पी.) की बहाली से इन्कार किया गया था।

चन्दा कोचर, जिनके नेतृत्व की पूर्व में बहुत प्रशंसा होती थी तथा उन्हें प्रतिष्ठित पद्म भूषण भी दिया गया था, के कैटीपर में अवरोध तब आया जब आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने एक अंदरूनी जांच करायी। इस जांच ने विडियोकोन ग्रुप के साथ उनके कार्यों व

(शेष पृष्ठ 5 पर)

प्र.मंत्री मोदी ने 2024 के आम चुनावों के लिए ''विकसित भारत'' नारा दिया

प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से भाजपा के मिशन 2024 की शुरूआत करेंगे

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 17 दिसम्बर से दो दिवसीय दौरा है। इस दौरान वह ''विकसित भारत'' थीम पर केन्द्रित ''मिशन-2024'' की शुरुआत करेंगे।

हाल ही सम्पन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और पार्टी सांसदों से ''विकसित भारत'' थीम को लेकर सुशासन और विकास पर फोकस करने को कहा है। धारा 370 और तीन तलाक के उन्मूलन जैसे चुनावी वादे निभाने के बाद भाजपा का उद्देश्य प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के संभावित तीसरे कार्यकाल में मतदाताओं को भारत के कायाकल्प और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश का दर्जा बढ़ाने के लिए तैयार करना है।

''इण्डिया'' गठबंधन के नेताओं ने जहां बढ़ती बेरोज़गारी और महंगाई पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है, वहीं भाजपा का प्रकट रूप से प्रयास भारतीय अर्थव्यवस्था की उज्जवल तस्वीर पेश करना है। यह कोई संयोग नहीं है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी शासन के दौरान की गई आर्थिक प्रगति के बारे में हाल ही विस्तार से बताया। उन्होंने कहा था कि ''वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान विश्व में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई और निर्माण सैक्टर में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि दर रही।''

सीतारमण ने यह भी कहा कि भारत, चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। उन्होंने प्रत्यक्ष कर संग्रहण का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है।'' इसके बावजूद बेरोज़गारी दूर करने में सरकार के समक्ष चुनौतियां अभी बरकरार है, लेकिन बताया जाता है कि युवा बेरोज़गारी की दर वर्ष 2017-18 में जहां 17.8 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2022-23 में गिरकर 10 प्रतिशत पर आ गई है। अगले वर्ष होने जा रहे लोकसभा चुनावों से पूर्व तक जीत का सिलसिला जारी रखने के उद्देश्य से भाजपा ने देश भर में ''विकसित भारत संकल्प यात्रा'' निकालने का निर्णय लिया ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने वाली मोदी सरकार की नीतियों से मिली सुविधाओं और फायदों के प्रति जनता को जागरुक किया जा सके।

प्रधानमंत्री वाराणसी में करीब एक हजार करोड़ रूपयों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों व सांसदों से कहा कि, वे जनता को बताएं कि भाजपा ने अपने चुनावी वायदों में धारा 370 को हटाने, तीन तलाक का खात्मा करने आदि को निभाया है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, तीसरा कार्यकाल मिला तो वे भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे।
- विपक्ष का ''इंडिया'' गठबंधन बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार और भाजपा को घेरने की तैयारी में है।

ई.वी.एम. की भूमिका फिर संदेह के घेरे में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। हाल ही

- मध्य प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों को विभिन्न बूथों पर 50-60 वोट मिलने पर हैरानी जताते हुए ई.वी. एम. की भूमिका पर सवालिया निशान लगाया।

सम्पन्न विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ई.वी.एम. की भूमिका

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कांग्रेस के पाले में अल्पसंख्यक वोट बैंक की वापसी से क्षेत्रीय दल और भाजपा चिंतित

कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। कांग्रेस को अल्पसंख्यकों अर्थात मुस्लिमों के वोट मिलने से क्षेत्रीय पार्टियां और यहां तक कि भाजपा भी चिन्तित है। कांग्रेस को मुस्लिमों के वोट कर्नाटक में मिलना शुरु हुए थे और यह सिलसिला तेलंगाना में भी जारी रहा।

कांग्रेस ने कर्नाटक में भाजपा को हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी चतुराई से घेरा था और एक सोची-समझी रिस्क लेकर घोषणा की थी कि वह यदि सत्ता में आई तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगी।

शुरु में तो ऐसा लगा था कि कांग्रेस यह वादा करके स्वयं को पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, लेकिन वह इसे लेकर सुनिश्चित थी कि इस वादे से अल्पसंख्यकों के वोट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसका कारण यह था कि मुस्लिमों को भाजपा से भय था और वे किसी संरक्षक की तलाश में थे और कांग्रेस में उन्हें वह संरक्षक नज़र आया।

अल्पसंख्यक समुदाय ने वस्तुतः जनता दल (सैक्यूलर) के क्षेत्रीय संतुलन को तिलांजलि दे दी। इस कारण

- कर्नाटक और तेलंगाना में अल्पसंख्यक वोट बैंक ने ही कांग्रेस को शानदार जीत दिलाई है।
- कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से हिन्दुत्व के मुद्दे पर भाजपा को घेरा कि, अल्पसंख्यकों ने जनता दल (सैकुलर) को भी छोड़ दिया।
- कांग्रेस ने तेलंगाना में भी यही रणनीति अपनाई जिसकी वजह से औवेसी की पार्टी को अपने गढ़ हैदराबाद में जूझना पड़ा था।

जनता दल (एस) 20 सीटें भी नहीं जीत सका। अब चूंकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव सन्निकट है, इसलिए कांग्रेस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसे ना केवल मुस्लिमों के बल्कि अन्य अल्पसंख्यकों के वोट भी प्राप्त हों और इसके लिए वह लक्षित समूहों के निरंतर सम्पर्क में है।

इस क्रम में ए.आई.सी.सी. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी और उनकी टीम अल्प-संख्यक वोटर्स को आकर्षित करने के कारण महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उनकी टीम ईसाई, सिख, बौद्ध और अन्य धर्मावलम्बियों के प्रभावी लोगों के सम्पर्क में हैं तथा सभ्य समाज के सदस्यों एवं एन.जी.ओज़. के भी सम्पर्क में है।

इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य हैं और कांग्रेस नेतृत्व द्वारा मैदान में उतारी गई टीम का हिस्सा है। इस बार हुए तेलंगाना विधानसभा चुनावों में उनकी टीम को जो क्षेत्र आवंटित हुए, वहां उसने जनता के साथ जुड़ाव रखकर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के लिए काम किया। इस टीम ने वोटर्स के उस विपरीत ध्रुवीकरण को भी

(शेष पृष्ठ 5 पर)

ADMISSION CLOSING SOON
B.A.-LL.B.
BIYANI LAW COLLEGE (Co-Ed.)
Affiliated to Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur
Helpline : +91-7737823249

अन्ततोगत्वा हो ही गया महुआ मोईत्रा का लोकसभा से निष्कासन

विपक्ष ने इसे लोकसभा के ''काले अध्याय'' की संज्ञा दी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। सत्तारुढ़ भाजपा ने अपने भारी भरकम बहुमत का सहारा लेकर तृणमूल कांग्रेस की निर्भीक सांसद महुआ मोईत्रा को संसद से निष्कासित करवा दिया। एथिक्स कमेटी ने महुआ पर सवाल पूछने के एवज में पैसे लेने का आरोप लगाया है तथा आरोप है कि उन्होंने संसद की आई डी व पासवर्ड एक उद्योगपति को देने का आरोप लगाते हुए उनके आचरण सांसद की भूमिका के प्रतिकूल ठहराया।

एथिक्स कमेटी ने जिस दिन जांच शुरु की थी उसी दिन से महुआ का निष्कासन तय था। यह स्पष्ट रुप से एक ऐसे विपक्षी सांसद को अनुशासित करने का मोईत्रा के अडानी ग्रुप के बारे में पूछे

- मोईत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की जांच शुरू होने के दिन से ही महुआ का लोकसभा से निष्कासन
- चर्चा है कि, मोईत्रा के अडानी और मोदी के संबंधों पर पूछे जाने वाले सवालों को लेकर सरकार बहुत असहज हो रही थी। इसलिए उन्हें यह सजा दी गई है।
- मोईत्रा पर आरोप है कि, उन्हें पैसे लेकर अडानी के खिलाफ सवाल पूछे तथा संसद की आई.डी. व पासवर्ड दुबई में रहने वाले व्यापारी से शेयर किए।
- एथिक्स पैनल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर जांच शुरू की। पैनल के विपक्षी सदस्य व मोईत्रा का आरोप है कि, मोईत्रा से पूछताछ के दौरान घटिया सवाल पूछे गए थे।

जाने वाले सवालो, खासकर मोदी व अडानी के रिश्ते पर सवाल करने से भाजपा सरकार बेहद नाराज है।

पैनल रिपोर्ट, जिसमें महुआ को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों के आधार पर आरोपी ठहराया गया है को स्वीकार करने के बाद ध्वनिमत से निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया। कांग्रेस व तृणमूल ने सि ''काला अध्याय'' बताया।

कांग्रेस नेता सोनिया व राहुल ने महुआ के साथ वॉक आउट किया।

मोईत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने रखा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इसे प्राकृति के न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। इस पर सांसद हीना गावित व अपराजिता सारंगी ने आरोप

(शेष पृष्ठ 5 पर)